



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2054]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2019/आषाढ़ 11, 1941
No. 2054]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2019/ASHADHA 11, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.आ. 2273(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.03.2019 की का.आ.सं. 1280 (अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें पैंतालीस (45) दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2 यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त सैंतीस (37) आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित जांच और सुनवाई बोर्ड ने विचार किया और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी किया।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

दिल्ली मुख्य योजना-2021		
क्र.सं.	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1.	अध्याय 5 व्यापार और वाणिज्य ; पैरा 5.6.3 क	
	क. ऐसे प्लॉटों के एफ.ए.आर. आवासीय प्लॉटिड विकास के संबंधित साइज हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. के समान होंगे अथवा पट्टा विलेख / हस्तांतरण विलेख / विक्रय विलेख/आवंटन की शर्तों में निर्धारित एफ.ए.आर. जो भी अधिक हो, के अनुसार होंगे। तथापि, यदि मौजूदा भवन में कुल एफ.ए.आर 100 वर्ग मीटर से अधिक तथा 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज पर अनुमेय एफ.ए.आर. से अधिक होता है, तो ऐसे अधिक एफ.ए.आर. (अधिकतम 350 एफ.ए.आर. तक) को लागू प्रभारों के 1.5 गुना जुर्माना प्रभारों के भुगतान की शर्त पर अनुमति दी जाएगी।	क. ऐसे प्लॉटों के एफ.ए.आर. आवासीय प्लॉटिड विकास के संबंधित साइज हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. के समान होंगे अथवा पट्टा विलेख / हस्तांतरण विलेख/विक्रय विलेख/आवंटन की शर्तों में निर्धारित एफ.ए.आर. जो भी अधिक हो, के अनुसार होंगे। तथापि, यदि मौजूदा भवन में कुल एफ.ए.आर 100 वर्ग मीटर से अधिक तथा 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज पर अनुमेय एफ.ए.आर. से अधिक होता है, तो ऐसे अधिक एफ.ए.आर. (अधिकतम 350 एफ.ए.आर. तक) को सरकार के अनुमोदन से यथा-निर्धारित जुर्माना प्रभारों के भुगतान की शर्त पर अनुमति दी जाएगी।
2.	अध्याय 15 : मिश्रित उपयोग विनियमन; पैरा 15.9(V)	
	(V) इस अधिसूचना की शर्तों के उल्लंघन में अथवा पंजीकरण के बिना मिश्रित उपयोग के अंतर्गत पाई गई सम्पत्तियों के मामले में संगत अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त मिश्रित उपयोग हेतु लागू प्रभारों के 1.5 गुना जुर्माने का स्थानीय निकाय को भुगतान करना होगा।	(V) इस अधिसूचना की शर्तों के उल्लंघन में अथवा पंजीकरण के बिना मिश्रित उपयोग के अंतर्गत पाई गई सम्पत्तियों के मामले में संगत अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त सरकार के अनुमोदन से यथा-निर्धारित जुर्माने का स्थानीय निकाय को भुगतान करना होगा।

[फा.सं. के-12016/1/2018-डीडी-1]

अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2019

S.O. 2273(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1280 (E) dated 09.03.2019 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five (45) days.

2. Whereas, thirty seven (37) numbers of objections / suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved in the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

S. No.	MPD-2021	
	Existing Provision	Proposed Modifications
1.	Chapter 5: Trade and Commerce; Para 5.6.3 a.	
	a. FAR of such plot shall be as prescribed for respective size of the residential plotted development or lease deed / conveyance deed / sale deed/allotment conditions, whichever is more. However, in case total FAR in the existing building is exceeding the permissible FAR on the plots of size above 100 sq.m and upto 250 sq.m., such excess FAR (upto max. 350 FAR) shall be permitted subject to payment of penalty charges amounting to 1.5 times the applicable charges.	a. FAR of such plot shall be as prescribed for respective size of the residential plotted development or lease deed / conveyance deed / sale deed / allotment conditions, whichever is more. However, in case total FAR in the existing building is exceeding the permissible FAR on the plots of size above 100 sq.m and upto 250 sq.m., such excess FAR (upto max. 350 FAR) shall be permitted subject to payment of penalty charges as prescribed with the approval of Government.
2.	Chapter 15: Mixed Use Regulations; Para 15.9 (v)	
	(v) In addition to other penal action available under the relevant act, properties found to be under mixed use, without registration or in violation of the terms of this notification shall be liable to pay, to the local body, a penalty amounting to 1.5 times the applicable charges for mixed use.	(v) In addition to other penal action available under the relevant act, properties found to be under mixed use, without registration or in violation of the terms of this notification shall be liable to pay, to the local body, a penalty as prescribed with the approval of Government.

[F. No. K-12016/1/2018-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.